पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2018 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 23099

चंदन कुमार, पिता - श्री भादो सिंह, गाँव तुलसियाही के निवासी, पुलिस थाना-
बख्तियारपुर, जिला-सहरसा।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. आयोग-सह-प्रधान सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, न्यू सचिवालय, पटना।
3. कलेक्टर, सिरसा, बिहार।
4. खान निरीक्षक-सह-सक्षम अधिकारी, सिरसा।

.... उत्तरदाता/ओं

उपस्थित:

याचिकाकर्ताओं के लिए:	श्री संजीव रंजन, अधिवक्ता सुश्री आस्था अनन्या,
राज्य के अधिवक्ता:	श्री ज्ञान प्रकाश ओझा-जी. ए.-7 श्री अभिनव अशोक,
खानों के लिए जी. ए.-7 के एसी:	श्री नरेश दीक्षित, एस. पी. पी. पी. माइंस श्री बृज बिहारी तिवारी, अधिवक्ता

रिट याचिका - खान आयुक्त द्वारा पारित उस आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा खान निरीक्षक द्वारा 2016 की नीलामी राशि पर 2017 में 20% वृद्धि की मांग को चुनौती देने वाले प्रत्यावेदन को खारिज कर दिया गया।

याचिकाकर्ता को 2016 में बालू खनन परियोजना के लिए उच्चतम बोलीदाता घोषित किया गया था। बोली राशि को प्रत्येक वर्ष 20% की दर से बढ़ाया जाना था।

याचिकाकर्ता ने 02.07.2016 को आवश्यक शुल्क जमा किया, लेकिन स्वीकृति आदेश जारी नहीं किया गया। अंततः, खान और भूविज्ञान विभाग ने खनन योजना को 27.12.2016 को स्वीकृत किया, यानी खनन योजना 29.07.2016 को प्रस्तुत किए जाने के पांच महीने बाद। इसके बाद, 23.01.2017 को पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया, जिसे 16.03.2017 को मंजूरी दी गई।

उपरोक्त परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने 2016 में जमा की गई निपटान राशि को 2017 के बकाया के खिलाफ समायोजित करने की मांग की।

निर्णय - याचिकाकर्ता 2016 में एक भी दिन के लिए बालू घाटों का संचालन नहीं कर सके, मुख्यतः क्योंकि खनन विभाग ने खनन योजना को स्वीकृति देने में देरी की, जो 27.12.2016 को जारी की गई और यह देरी राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति देने में और बढ़ाई गई। फिर भी, राज्य याचिकाकर्ता को लाभ से वंचित करते हुए वह राशि जब्त करना चाहता है और उसे बिना किसी गलती के दंडित कर रहा है। (पैरा 37)

उत्तरदायी प्राधिकरण 2016 में खनन कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक स्वीकृति आदेश समय पर देने में असफल रहे और विभिन्न अनुबंधों के बहाने याचिकाकर्ता से जबरन भुगतान की मांग नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 20% वृद्धि की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि वास्तविक संचालन उत्तरदाताओं द्वारा दी गई पर्यावरणीय स्वीकृति के बाद हुआ। जहां तक अन्य मांगों का सवाल है, याचिकाकर्ता उन शर्तों के अनुरूप भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे, जिन्हें उन्होंने स्वीकार किया। (पैरा 42)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय

मौखिक निर्णय

दिनांक: 22-07-2024

पक्षों को सुना।

2. वर्तमान याचिका को निम्नलिखित राहतों के अनुदान के लिए प्राथमिकता दी गई है:

(i) विविध वाद संख्या 17/2018 में खान आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा पारित दिनांक 5.11.2018 के आदेश को रद्द करने के लिए, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा खान निरीक्षक-

सह-सक्षम प्राधिकारी सुपौल द्वारा 2016 की नीलामी राशि पर 2017 में 20% की बढ़ी हुई बोली राशि का भुगतान करने के लिए उठाए गए मांग पर सवाल उठाते हुए प्रस्तुत अभ्यावेदन, 2016 को बंदोबस्त का वर्ष मानकर और परिणामस्वरूप 2018 के लिए नीलामी राशि को आनुपातिक रूप से 20% कम करके 2017 को बंदोबस्त का प्रथम वर्ष मानकर खारिज कर दिया गया है और 19.12.2017 से 29.1.2018 की अवधि के लिए नीलामी राशि की आनुपातिक राशि के भुगतान से छूट के लिए जो आदेश अवैध और अस्थिर है,

(ii) सक्षम पदाधिकारी-सह-खान निरीक्षक, जिला खान कार्यालय, सहरसा के हस्ताक्षर से जारी पत्र संख्या 105/एम दिनांक 8.12.2017 के एक भाग को इस सीमा तक निरस्त करने के लिए कि कार्य आदेश में 2017 के लिए नीलामी राशि पिछले वर्ष की तुलना में 20% बढ़ाकर मनमाने ढंग से तय की गई है, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध और इस प्रकार प्रतिवादी अधिकारियों ने सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 6526/2017 में पारित आदेश दिनांक 10.11.2017 की अवहेलना और उसके प्रतिकूल कार्य किया है, जो अवैध और अस्थिर है;

(iii) प्रतिवादी अधिकारियों को नीलामी राशि को पिछले वर्ष 2017 की तुलना में 20% बढ़ाने से रोकने के लिए परमादेश याचिका दायर की गई है क्योंकि प्रतिवादी की गलती के कारण याचिकाकर्ता को कार्य आदेश जारी नहीं किया

गया था और इस प्रकार निपटान की अवधि नीलामी की तारीख से नहीं बल्कि कार्य आदेश की तारीख से शुरू मानी जानी चाहिए;

(iv) सक्षम पदाधिकारी-सह-खान निरीक्षक, जिला खान कार्यालय, सहरसा के हस्ताक्षर से जारी पत्र संख्या 242 दिनांक 26.2.2018 को निरस्त करने के लिए, जिसके तहत प्रतिवादी अधिकारियों ने सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 6526/2017 में पारित आदेश दिनांक 10.11.2017 की अवहेलना करते हुए बंदोबस्ती के तीसरे वर्ष के रूप में मानते हुए पिछले वर्ष यानी 2017 की तुलना में नीलामी राशि में 20% की वृद्धि की थी और प्रतिवादी को 2016 की नीलामी राशि पर केवल 20% चार्ज करने के लिए प्रतिबंधित किया था। परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जारी 25.6.2018 की मांग सूचना को भी इस सीमा तक निरस्त किया जा सकता है कि उसने अवैध रूप से बंदोबस्ती राशि में 40% की वृद्धि की थी और छूट देने से इनकार कर दिया था;

(v) उक्त पत्र संख्या 242 दिनांक 26.2.2018 को इस सीमा तक निरस्त करने के लिए, जिसके द्वारा यह माना गया था कि याचिकाकर्ता उक्त अवधि के लिए छूट का दावा करने का हकदार नहीं है, प्रतिवादी द्वारा ई-चालान को अवरुद्ध करके खनन कार्य को जानबूझकर बंद कर दिया गया था।

(vi) याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता 19 दिसंबर 2017 से 29.1.2018 के

बीच की अवधि के लिए नीलामी राशि के आनुपातिक भुगतान से छूट का हकदार है, जब ट्रांजिट चालान विभाग द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था और परिणामस्वरूप कोई खनन कार्य नहीं किया जा सका और इसे भविष्य के भुगतान के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है।

3. याचिकाकर्ता के अनुसार मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:

4. 5 साल की अवधि के लिए सहारसा जिले में बालुघाट के निपटारे के लिए प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार, याचिकाकर्ता और 2 अन्य बोलीदाताओं ने अपना बोली दस्तावेज प्रस्तुत किया।

5. सभी 3 बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत बोली को 21.06.2016 पर तकनीकी समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने 23.06.2016 पर आयोजित खुली प्रतिस्पर्धी बोली में भाग लिया। याचिकाकर्ता को सबसे अधिक बोली लगाने वाला घोषित किया गया था क्योंकि उसने पहले वर्ष के लिए 46 लाख 80 हजार रुपये की पेशकश की थी, जिसे बाद के प्रत्येक वर्ष में 20 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाएगा।

6. तदनुसार, निविदा समिति ने याचिकाकर्ता के पक्ष में बोली का निपटारा किया और खान निरीक्षक-सह-सक्षम अधिकारी ने पत्र संख्या 409/खान दिनांक 30.06.2016 के माध्यम से परिणामी पत्र जारी किया, जिसमें 2016 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए सहारसा जिले में बालूघाट के बंदोबस्त के बारे में शामिल किया गया था। याचिकाकर्ता को निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार आवश्यक राशि जमा करनी थी और पर्यावरण मंजूरी भी लेनी थी और कलेक्टर द्वारा अनुमोदन के बाद, समझौता निष्पादित किया जा सकता था।

7. इसके अलावा, दिनांकित 21.06.2016 पत्र के खंड (xiii) और (xv) के अनुसार, सफल निविदाकार को एक अनुमोदित खनन योजना और पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता होती है और केवल खनन योजना और पर्यावरण मंजूरी के अनुमोदन के बाद, पट्टे को मंजूरी देने वाला कार्य आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना था। इस प्रकार, मूल

मंजूरी आदेश/कार्य आदेश जारी करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त यह थी कि पट्टेदार को राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति से एक अनुमोदित खनन योजना और पर्यावरण मंजूरी प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

8. तदनुसार, याचिकाकर्ता ने दिनांकित 30.06.2016 पत्र में निर्धारित 02.07.2016 पर निर्धारित समय के भीतर आवश्यक प्रतिभूति जमा और अन्य देय करों के साथ अग्रिम किस्त जमा की।

9. इसके बाद, बिहार लघु खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2014 (अब से, 'नियम 2014') के नियम 24 (3) और (7) के संदर्भ में याचिकाकर्ता ने 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर सहरसा रेत खानों की प्रगतिशील खानों को बंद करने के साथ खनन योजना की पांच प्रतियां निदेशक, खान और भूविज्ञान, बिहार, पटना को प्रस्तुत करे और निदेशक के कार्यालय की रसीद के प्रतीक के रूप में प्राप्तियां जारी की।

10. हालाँकि, यह केवल 27.12.2016 पर ही था, यानी पाँच महीने के बाद कि खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार, पटना ने सहरसा रेत जमा की प्रगतिशील खदान बंद करने की योजना के साथ खनन योजना को मंजूरी दी।

11. इसके बाद याचिकाकर्ता ने 23.01.2017 को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (इसके बाद से प्राधिकरण) के समक्ष प्रस्तावक रेत खनन परियोजना के लिए 4 बिंदुओं पर पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन दायर किया। प्राधिकरण ने 18 और 19 फरवरी, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में सहरसा जिले के सुरसारी नदी, तिलावे नदी पर तुलसियाघाट और तिलावे नदी पर डंका भपटिया घाट नामक 3 परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की अनुशंसा की। एसईएसी की अनुशंसा के आधार पर एसईआईए ने 16.3.2017 को सूचित किया।

12. इसके बाद याचिकाकर्ता ने 3 परियोजनाओं के संबंध में खनन पट्टे को मंजूरी देने हेतु कार्य आदेश जारी करने के लिए खदान निरीक्षक-सह-सक्षम अधिकारी, सिरसा को दिनांक 21.3.2017 का अभ्यावेदन दायर किया क्योंकि उन्होंने पत्र/आदेश में परिकल्पित सभी पूर्व-आवश्यकताओं को पूरा किया था।

13. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि नियम 11ए(सी) के अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 के लिए नीलामी राशि का 25% जमा करने के बाद खनन पट्टे को मंजूरी देने के लिए मुख्य स्वीकृति आदेश जारी करना अनिवार्य था, लेकिन वर्ष 2016 में इसे कभी जारी नहीं किया गया। इस प्रकार, वर्ष 2016 में पट्टे को मंजूरी देने के लिए मुख्य स्वीकृति आदेश यानी कार्य आदेश जारी न करने में सक्षम प्राधिकारी की विफलता का अर्थ है कि वर्ष 2016 में याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई समझौता नहीं किया गया था।

14. चूंकि आवश्यक मंजूरी आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी कोई कार्य आदेश जारी नहीं किया जा रहा था, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा पटना उच्च न्यायालय के समक्ष सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 6526/2017 प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादियों ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को कार्य आदेश जारी करने से पहले वर्ष 2016 के लिए शेष नीलामी राशि और वर्ष 2017 के लिए 20% बढ़ी हुई नीलामी राशि जमा करना आवश्यक था क्योंकि विभाग द्वारा वैधानिक अनुमोदन प्रदान करने में देरी के बावजूद निपटान की अवधि नीलामी की तारीख से शुरू होगी।

15. सीडब्ल्यूजेसी संख्या 6526/2017 में प्रति शपथ पत्र के पैराग्राफ संख्या 13 में निम्न प्रकार लिखा है:-

“यहाँ ऊपर वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में तथा याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया है कि कार्य आदेश देने में देरी याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं की गई थी, जिसमें प्रतिवादियों की कोई गलती नहीं थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि नई रेत नीति और इस संबंध में विधि विभाग, बिहार की राय (वेस्टलिक प्राइवेट लिमिटेड के मामले में) के अनुसार याचिकाकर्ता को कार्य आदेश जारी करने से पहले वर्ष 2017 के लिए आवश्यक किश्तें और अन्य जमा राशि जमा करनी होगी। यदि याचिकाकर्ता द्वारा आवश्यक किश्तें और अन्य

जमा राशि जमा कर दी जाती है और उसके बाद प्रतिवादी रेत की खदान के लिए तत्काल कार्य आदेश जारी करेंगे, तो कोई कार्य आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।

16. पक्षकारों को सुनने के बाद, इस माननीय न्यायालय ने 2017 के C.W.J.C.No.6526 में पारित एक आदेश दिनांकित 10.11.2017 के माध्यम से निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"मेरे विचार में, जिन परिस्थितियों पर चर्चा की गई है, उनसे यह पुष्टि होती है कि राज्य अपने सबसे खराब स्तर पर मुकदमा कर रहा है, जबकि यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता 2016 में एक दिन भी बालू घाटों का संचालन नहीं कर सका, मुख्यतः इसलिए क्योंकि खनन विभाग ने 27.12.2016 को जारी खनन योजना को मंजूरी देने में देरी की और राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, बिहार ने पर्यावरण मंजूरी देने में देरी की। राज्य अभी भी याचिकाकर्ता को लाभ से वंचित करके और बिना किसी गलती के याचिकाकर्ता को दंडित करके उस राशि को अपने पास रखना चाहता है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। अन्यायपूर्ण समृद्धि का सिद्धांत सभी पर लागू होता है और वर्तमान मामले में राज्य को एक वास्तविक निवासी की कीमत पर अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इन परिस्थितियों में यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है। खनन विभाग के अधिकारी, विशेष रूप से प्रतिवादी तदनुसार, क्रमांक 3 और 4 को निर्देश दिया जाता है कि वे

इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/पेश होने के 4 सप्ताह के भीतर, विधि के अनुसार, वर्ष 2016 के लिए याचिकाकर्ता से प्राप्त निपटान राशि को समायोजित करने के पश्चात, वर्ष 2017 की शेष अवधि के लिए, यह ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2017 में भी 11 महीने से अधिक समय बीत चुका है, नई मांग प्रस्तुत करें।

17. यह बताना प्रासंगिक है कि 10.11.2017 दिनांकित आदेश के अनुसार C.W.J.C.No 6526/2017 में हालांकि, राज्य के अधिकारियों ने एक अतिरिक्त राशि को जेब में डालने के इरादे से, जिसे याचिकाकर्ता उपरोक्त आदेश के संदर्भ में भुगतान करने का हकदार नहीं था, नीलामी राशि को पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया, जैसे कि यह निपटान 2016 से शुरू हुआ था, यानी नीलामी की तारीख से। याचिकाकर्ता को जानबूझकर वर्ष 2016 में खनन की अनुमति नहीं दी गयी। प्रत्यार्थी न० 4 पत्रांक 105/M दिनांक 08.12.2017 के अनुसार 2017 वर्ष के शेष समय के लिए कार्य आदेश जारी करेंगे। प्रतिवादी पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि प्राप्त करके याचिकाकर्ता को दंडित करना चाहते थे। तर्क यह है कि जब वर्ष 2016 के लिए उठाई गई मांग को पटना उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था, तो 20 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि को भी रद्द कर दिया गया था क्योंकि न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को 2017 की शेष अवधि के लिए नई मांग उठाने का निर्देश दिया था, प्रतिवादी वर्ष 2016 को आधार वर्ष के रूप में लेते हुए 20 प्रतिशत की वृद्धि में हाथ नहीं मिला सकते हैं जैसा कि वर्ष 2017 से किया जाना है।

18. आगे का विवाद यह है कि खनन कार्य शुरू होने के 10 दिनों के बाद विभाग ने 19.12.2018 पर पारगमन चालन को अवरुद्ध कर दिया, जिससे सहारसा जिले में खनन कार्य बंद हो गया। याचिकाकर्ता ने इस प्रकार प्रतिवादी नं. 4. सहारसा जिले में खनन कार्य बंद करने के लिए कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं था।

19. यह कहना और भी प्रासंगिक है कि ई-चालान को अंततः 30.1.2018 पर सहरसा जिले के लिए बहाल कर दिया गया और उसके बाद याचिकाकर्ता ने फिर से अपना खनन कार्य शुरू कर दिया। इस प्रकार वह 19.12.2017 से 30.01.2018 अवधि के लिए छूट का भी हकदार था, जब खनन कार्य प्रत्यर्थी द्वारा बिना किसी कारण के ई-चालान की नाकाबंदी का लेखा बंद कर दिया गया था। हालांकि विभाग का रुख यह है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण चालान को अवरुद्ध कर दिया गया था, लेकिन तथ्य यह है कि इसे उपरोक्त अवधि के लिए अवरुद्ध कर दिया गया था जिसे विभाग के पी. यू. अनुभाग से सत्यापित किया जा सकता है।

20. हालांकि, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पत्र संख्या VIII के तहत दिनांक 25.6.2018 को मांग नोटिस जारी किया गया, जिसमें उसे नीलामी राशि की दूसरी किस्त के रूप में 16,84,800/- रुपये और अन्य वैधानिक बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें 2018 में नीलामी राशि में 40% से अधिक की वृद्धि की गई थी, क्योंकि अधिकारियों ने उस अवधि के लिए छूट देने से इनकार कर दिया था, खनन कार्य बंद कर दिया गया था।

21. याचिकाकर्ता ने खान निरीक्षक-सह-सक्षम पदाधिकारी, सहरसा के हस्ताक्षर से जारी दिनांक 08.12.2017 और 26.02.2018 के उपरोक्त पत्रों को सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 14814/2018 के तहत रिट याचिका दायर करके चुनौती दी थी। इसका निपटारा 14.09.2018 को किया गया जिसमें याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर प्रतिवादी प्रधान सचिव-सह-खान आयुक्त, बिहार से संपर्क करने की छूट दी गई, जो इस न्यायालय द्वारा 10.11.2017 को दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए एक तर्कसंगत आदेश द्वारा चार सप्ताह के भीतर इसका निपटारा करेंगे। तब तक याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया।

22. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने मामले को उठाया और आदेश/ज्ञापन सं. 4190 दिनांक 4190 ने एकमात्र आधार पर अभ्यावेदन को खारिज कर दिया कि विभिन्न खंडों को स्वीकार करते हुए दस्तावे पर हस्ताक्षर करने के बाद,

यह आधार वर्ष 2016 को लेते हुए 20 प्रतिशत की बढ़ी हुई मांग का दावा नहीं कर सकता है।

23. व्यथित, वर्तमान याचिका।

24. प्रत्यर्थी का यह कहना कि जवाबी हलफनामे के अनुसार 3 और 4 इस प्रकार हैं:

"7. याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चूंकि सार्वजनिक नीलामी वर्ष 2016 में की गई थी और कार्य आदेश दिसंबर 2017 में जारी किया गया था, इसलिए वर्ष 2017 को निपटान का पहला वर्ष माना जा सकता है और उसके बाद किशतों पर 20 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। यह तथ्य अन्यथा है। कार्य आदेश तभी दिया जाता है जब अधिवासी सक्षम प्राधिकारी से एक अनुमोदित खनन योजना और पर्यावरण मंजूरी प्रस्तुत करता है और इस प्रक्रिया में उत्तर देने वाले उत्तरदाता किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। यह निपटानकर्ता/याचिकाकर्ता पर है कि वह ऐसे दस्तावेज जमा करे और कार्य आदेश प्राप्त करने में कोई भी देरी पूरी तरह से याचिकाकर्ता पर है।

8. कि प्रतिवादी अधिकारी निविदा दस्तावेज और समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार कदम उठाए हैं और मांग/किशतें उठाई हैं। कि याचिकाकर्ता ने सी. डब्ल्यू. जे. सी. एन. ओ. वाली एक रिट याचिका दायर की। 2018 का 14814, जिसे इस माननीय न्यायालय द्वारा सुना गया था और याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतों के लिए आयुक्त, खान से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

9. कि याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन दायर किया और याचिकाकर्ता के वकील की उपस्थिति में मामले की सुनवाई की गई। वह एक गड़बड़ है। पक्षकारों को से सुनने और निविदा के नियमों और शर्तों पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता और खान आयुक्त, के आवेदन पर मामला संख्या 17/2018 शुरू किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका में तत्काल आदेश दिनांक 5/11/218 को चुनौती दी गई है।

11. कि आयुक्त, खान, बिहार निविदा दस्तावेज के उपरोक्त प्रावधानों पर विचार कर रहे हैं, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा नियम और शर्तों का पालन करने के लिए सहमति देते हुए विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें यह भी इंगित किया गया है कि याचिकाकर्ता को किशतों के जमा भुगतान के तरीके/प्रक्रिया के बारे में जानकारी है। उसी की जानकारी होने के बाद याचिकाकर्ता अपनी हस्ताक्षरित सहमति देने के बाद इस माननीय न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देना।

12. कि उपरोक्त मुद्दे के अलावा याचिकाकर्ता द्वारा कुछ अवधि की छूट और किस्त राशि में तदनुसार समायोजन के लिए एक और प्रार्थना की गई है। निविदा दस्तावेज का वह खंड 19 (xii) इस मुद्दे के बारे में स्पष्ट रूप से बताता है कि खनन गतिविधि में किसी भी प्रकार के व्यवधान के लिए मुआवजे या छूट का कोई प्रावधान नहीं है। कि प्रत्यर्थी राज्य किसी

भी प्रकार के मुआवजे के किसी भी दावे को स्वीकार करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को आयुक्त, खान, बिहार द्वारा विविध भाषाओं में पारित अपने आदेश दिनांक 5/11/2018 में विधिवत खारिज कर दिया गया था। केस नं. 1 7/2018. कि याचिकाकर्ता ने उसमें निर्धारित टी. आर. ए. (टन प्रति वर्ष) के साथ एक ई. सी. प्राप्त किया है और इस तरह वह कैलेंडर वर्ष के भीतर किसी भी समय ऐसी निर्धारित सीमा की खुदाई खनन कर सकता है, इसलिए याचिकाकर्ता को इस खाते में भी नुकसान नहीं है।

13. कि 5/11/2018 दिनांकित आदेश विविध रूप में पारित हुआ। केस नं. 17/2018 आयुक्त, खान, बिहार द्वारा एक विस्तृत और तर्कपूर्ण आदेश है जो नियमों और नियमों और प्रावधानों की शर्तों का संकेत देता है इसलिए यह कानूनी रूप से सही है और कानून के अनुसार है।"

25. विद्वान विशेष पी.पी. माइंस ने प्रतिवादी संख्या 2 के निर्णय का बचाव प्रति शपथ पत्र के माध्यम से किया और उनका कहना है कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद याचिकाकर्ता वर्ष 2016 के लिए छूट की मांग नहीं कर सकता है। आगे यह भी कहा गया है कि पटना उच्च न्यायालय का दिनांक 10.11.2017 का पहला आदेश दिनांक 14.09.2018 के आदेश अर्थात् दूसरे आदेश के साथ विलय हो गया है और इस प्रकार याचिकाकर्ता पहले आदेश के आधार पर छूट का दावा नहीं कर सकता है।

26. विद्वान विशेष पी.पी. माइंस ने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश के समर्थन में कहा कि, 2 ने इस न्यायालय को पटना उच्च न्यायालय (डिवीजन बेंच) के एलपीए संख्या 379/2019 में सीडब्ल्यूजेसी संख्या

12859/2017 (श्री अमन सेठी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) के आदेश का संदर्भ देते हुए पैराग्राफ 24 और 25 का हवाला दिया है, जो इस प्रकार है:

24. "इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने पट्टे के नियमों और शर्तों के साथ-साथ अधिनियम और नियमों के बारे में पूरी तरह से अवगत होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक संदर्भ के लंबित होने को देखते हुए इसे चुनौती देने का फैसला किया, जिसे याचिकाकर्ता को उम्मीद थी कि अंततः उसके पक्ष में जवाब दिया जाएगा। भविष्य में मुकदमेबाजी में सफल होने की याचिकाकर्ता की यह आशा और अपेक्षा उसे के तुरंत बाद पट्टे को पंजीकृत कराने के समकालीन दायित्व से मुक्त नहीं कर सकती है। निष्पादन जो स्पष्ट रूप से स्टाम्प शुल्क के भुगतान पर निर्भर होगा और इसलिए, याचिकाकर्ता स्व शुल्क देने के लिए कानूनी दायित्व के तहत था, बशर्ते कि उसकी आपत्तियों को स्वीकार किया जाए जो मुकदमे में अन्यथा जो उसके द्वारा पसंद किया गया हो। इसलिए यह याचिकाकर्ता द्वारा अपनी मुकदमेबाजी की खोज के माध्यम से किया गया एक स्पष्ट स्वैच्छिक जोखिम था जिसे वह न्यायिक समीक्षा की मांग करने के अधिकार के रूप में आगे बढ़ाने का कानूनी रूप से हकदार है कि क्या उप-पंजीयक को अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की मांग करने का अधिकार था या नहीं, यह 2016 की संख्या 7034 की विषय वस्तु है जो बदले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे के परिणाम पर निर्भर है जैसा कि उसमें पारित किए गए अंतरिम आदेश में निर्दिष्ट किया गया

है, लेकिन यह अपने आप में याचिकाकर्ता को समझौते को पंजीकृत कराने या स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त करने के लिए कोई लाभ नहीं दे सकता है। इसलिए उस गिनती में कोई भी देरी याचिकाकर्ता के स्वैच्छिक जोखिम की कीमत पर है जिसने स्टाम्प शुल्क लगाने की वैधता को चुनौती देने का विकल्प चुना है। भविष्य में सफलता की उम्मीद के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क की वापसी हो सकती है जो याचिकाकर्ता द्वारा चलाए जा रहे मुकदमे का सबसे अच्छा संभव परिणाम हो सकता है। इस अटकलबाजी के आधार पर पट्टे की शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। यह वकील द्वारा सूचित किया जाता है। राज्य ने कहा कि क्षेत्र के सभी पट्टा धारकों ने अपने पट्टे पंजीकृत करवा लिए थे, सिवाय उस याचिकाकर्ता के जो मुद्रांक शुल्क के अधिरोपण का विरोध कर रहा था। याचिकाकर्ता को न्यायिक समीक्षा का अधिकार हो सकता है लेकिन यह तब तक स्टाम्प शुल्क के दायित्व को समाप्त नहीं करता है जब तक कि अन्यथा आदेश नहीं दिया जाता है।

25. कार्यकाल के विस्तार या अन्यथा का प्रश्न अनुबंध के नियमों और शर्तों पर निर्भर हो सकता है जिन्हें राज्य सरकार के अलावा किसी और द्वारा अपीलार्थी के लाभ के लिए परिभाषित या बदला जा सकता है। यह वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर न्यायिक समीक्षा के माध्यम से नहीं हो सकता है। उबेरॉय मोहिंदर सिंह और एसोसिएट्स बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा (1991) 2 एस. सी. सी. 362 में रिपोर्ट किया गया निर्णय, वर्तमान मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थी की सहायता के लिए नहीं आता है, जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है। पंजीकरण विभाग द्वारा स्टाम्प शुल्क की मांग को गैरकानूनी बाधा या चूक या अन्यायपूर्ण कार्य नहीं कहा जा सकता है जब तक कि मांग को गैरकानूनी नहीं माना जाता है। वह चरण अभी तक नहीं आया है।"

27. जवाब में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह न्यायालय उसी आदेश के पैराग्राफ 22 को प्रस्तुत करते हैं और प्रस्तुत करता है कि यह आदेश में शामिल किया गया था कि याचिकाकर्ता अंततः सफल होने की स्थिति में छूट या रियायत के अधिकार का दावा कर सकता है। उनका निवेदन है कि वे सी. डब्ल्यू. जे. सी. नं. 6526/2017 (चंदन कुमार बनाम राज्य) में सफल हुए और इस तरह, छूट/रियायत के हकदार थे। श्री अमन सेठी (सुप्रा) आदेश के प्रासंगिक अनुच्छेद 22 को शामिल करना उचित होगा जो इस प्रकार है:

"22. हमारी राय में, उत्तरदाता इस स्थिति का विरोध कर रहे थे और उन्होंने याचिकाकर्ता को कोई रियायत नहीं दी थी, लेकिन साथ ही वे उपरोक्त कारणों से पट्टे को रद्द करने में सक्षम नहीं प्रतीत होते हैं। नतीजतन, खनन विभाग की ओर से कोई चूक नहीं हुई ताकि उनकी ओर से किसी भी कमी को पूरा किया जा सके। उच्च न्यायालय ने 19.11.2016 पर अंतरिम आदेश पारित करते समय भी याचिकाकर्ता को छूट नहीं दी या स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं करने के उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। इसके

विपरीत, अदालत ने याचिकाकर्ता को पट्टे का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए उप-पंजीयक के पक्ष में बैंक गारंटी का विस्तार करने के लिए मजबूर किया। इसलिए, याचिकाकर्ता केवल उस स्थिति में छूट या रियायत के अधिकार का दावा कर सकता है जब वह 2016 के C.W.J.C. संख्या 7034 में सफल होता है और उससे पहले नहीं।” (माइन को रेखांकित करें)।

28. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुनने के साथ-साथ विद्वान विशेष पी. पी. माइंस, जिन तथ्यों विवाद नहीं है, वे इस प्रकार हैं:-

29. याचिकाकर्ता सहरसा जिले के तीन बालू घाटों के लिए सफल बोलीदाता था क्योंकि उसे सबसे ऊंची बोली लगाने वाला घोषित किया गया था। यह 2016-2019 की अवधि के लिए था और एक खंड के अनुसार, राशि को हर साल बीस प्रतिशत बढ़ाया जाना था।

30. याचिकाकर्ता ने 02.07.2016 पर आवश्यक शुल्क जमा किया लेकिन मंजूरी आदेश जारी नहीं किया गया। अंत में, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार, पटना ने खनन योजना को केवल 27.12.2016 यानी 29.07.2016 पर खनन योजना प्रस्तुत किए 'जाने के पांच महीने बाद ही मंजूरी दी। इसके बाद 23.01.2017 पर पर्यावरण मंजूरी आवेदन के लिए आवेदन किया गया जिसे 16.03.2017 पर मंजूरी दी गई। (रिट याचिका का अनुलग्नक-7)। उपरोक्त परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता 2017 के बकाया के मुकाबले वर्ष 2016 में जमा की गई निपटान राशि का समायोजन चाहता था।

31. याचिकाकर्ता ने बाद में **सीडब्ल्यूजेसी संख्या 6526/2017 (चंदन कुमार बनाम बिहार राज्य)** में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसका निपटारा 10.11.2017 को इस न्यायालय की पीठ (माननीय न्यायमूर्ति ज्योति सरन, जैसा कि उस समय उनके प्रभुत्व में था) द्वारा किया गया और रिट याचिका को निम्नलिखित अवलोकन के साथ अनुमति दी गई:-

“मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और मैंने अभिलेखों का अवलोकन किया है और जबकि याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रंजन का यह तर्क है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादियों की देरी से की गई कार्रवाई से पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता है, खनन विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री ललन कुमार का तर्क है कि विभाग द्वारा प्राप्त राय के मद्देनजर अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

मेरी राय में, चर्चा की गई परिस्थितियाँ इस बात की पुष्टि करती हैं कि राज्य अपने सबसे खराब स्तर पर मुकदमा कर रहा है, यहाँ तक कि जब यह इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता वर्ष 2016 में एक दिन भी बालू घाटों का संचालन नहीं कर सका, मुख्यतः इसलिए क्योंकि खनन विभाग ने खनन योजना को मंजूरी देने में देरी की, जो 27.12.2016 को जारी की गई थी और राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, बिहार ने पर्यावरण मंजूरी देने में देरी करके इस देरी को जारी रखा। राज्य अभी भी याचिकाकर्ता को लाभ देने से इनकार करके और बिना किसी गलती के याचिकाकर्ता को दंडित करके उस राशि को अपने पास रखना चाहता है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत सभी पर लागू होता है और वर्तमान मामले में राज्य को एक वास्तविक बंदोबस्तधारी की कीमत

पर अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इन परिस्थितियों में यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है। खनन विभाग के अधिकारियों, विशेषकर प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को तदनुसार, इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/पेश होने के 4 सप्ताह के भीतर, कानून के अनुसार, वर्ष 2016 के लिए याचिकाकर्ता से प्राप्त निपटान राशि को समायोजित करने के बाद, वर्ष 2017 की शेष अवधि के लिए नई मांग प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, यह ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2017 में भी 11 महीने से अधिक समय बीत चुका है।

32. याचिकाकर्ता का मामला है कि बाद में, वर्ष 2017 की शेष अवधि के लिए कार्य आदेश जारी किया गया था, लेकिन फिर से उनके खनन संचालन को आधार वर्ष 2016 से सक्रिय मानते हुए, 20 प्रतिशत राशि की मांग की गई थी। इसके अलावा, खनन कार्य को 19.12.2017 पर भी अवरुद्ध कर दिया गया था जिसे अंततः 30.01.2018 पर बहाल कर दिया गया था और इस प्रकार 19.12.2017 से 29.01.2018 के बीच की अवधि में कोई खनन कार्य नहीं हुआ था।

33. याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं के समक्ष आधार वर्ष 2017 पर विचार करने के लिए आंदोलन करता रहा और उस संक्षिप्त अवधि के लिए रियायत भी देता रहा जब खनन संचालन अवरुद्ध लेकिन बिना किसी सफलता के। इसके बाद, पत्र संख्या के माध्यम से की गई पिछली मांग को जारी रखते हुए। 105 दिनांकित (आई. डी. 1) (रिट याचिका का अनुलग्नक-10), एक अन्य पत्र नं. 242 दिनांकित 26.02.2018 जिला खनन कार्यालय, सिरसा द्वारा जारी किया गया था जिसमें पिछली रिट याचिका में दिए गए निर्देश की अनदेखी करते हुए, 2016 को आधार वर्ष मानते हुए मांग की गई थी।

34. याचिकाकर्ता ने 2018 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 14814 में इस न्यायालय का रुख किया जिसका निपटान 14.09.2018 पर किया गया और संक्षिप्त आदेश इस प्रकार है:-

“पक्षकारों के विद्वान वकील इस बात पर सहमत हैं कि वर्तमान रिट याचिका में शामिल विवाद को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय के दिनांक 10.11.2017 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 6526/2017 में पारित पूर्व निर्णय के आलोक में बेहतर ढंग से निपटाया जा सकता है।

2. उपर्युक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को आज से दो सप्ताह के भीतर प्रतिवादी संख्या 2 से संपर्क करने और एक विस्तृत अभ्यावेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता दी जाती है, जिसका निपटारा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय के दिनांक 10.11.2017 के उपर्युक्त निर्णय पर विचार करते हुए चार सप्ताह के भीतर एक तर्कसंगत और बोलने वाले आदेश द्वारा किया जाएगा। याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के निपटारे तक, संबंधित अधिकारी 20% बढ़ी हुई राशि के लिए कोई बिल नहीं बनाएंगे।”

35. इसके बाद मामला प्रतिवादी, प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के समक्ष गया और पक्षों (चंदन कुमार बनाम कलेक्टर, सहरसा एवं अन्य) को सुनने के बाद, एक आदेश पारित किया गया और याचिकाकर्ता को ज्ञापन संख्या 4190 दिनांक 05.11.2018 के माध्यम से सूचित किया गया, जिसके द्वारा प्रतिवादी, प्रधान सचिव ने माना कि याचिकाकर्ता ने नियम और शर्तों को स्वीकार कर लिया है और अब उसे वापस लौटने और रियायत मांगने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रधान सचिव द्वारा पारित आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे शामिल किया गया है:

"दोनों पक्षों को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों दोनों को देखा। सहरसा जिला के सम्पूर्ण मटकी मदोबस्ती बेचाग वर्ष 2016 से 31.12.2010 तक के लिए जून 2016 में निविदा आमंत्रित की गई की। निविदा दस्तावेज में बालूघाटों की बंदोबस्ती के लिए शर्त एवं समाज की करिव में निम्न शर्त है-

(क)

(1) निविदा के शर्तों एवं बंधनों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर के साथ हस्ताक्षर ।

(स) निविदा आवेदन पर मुहर के साथ हस्ताक्षर।

निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर तात्पर्य है कि निविदादाताको निविदा की सभी शर्तें नाम्य है । निविदा दस्तावेज की कडिका 4 में उल्लिखित है कि बालूघाटों की बंदोबस्ती पंचांग वर्ष 2016 से 31.12.2019 तक के लिए मान्य होगी। द्वितीय वर्ष तथा उसके आगे के दर्द के पूर्व के वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत के समतुल्य होगी। पार्टी कडिका 12 में बंदोबस्तधारी द्वारा भुगतान की प्रक्रिया का उल्लेख है। निविदा दस्तावेज की कडिका-19 (xiii) यह उद्यत है कि सरल निविदादाता को विभागीय अधिसूचना सं०-2887/ एम०,दिनांक-2207.2014 में उल्लेखित संचालन के नियम एवं शर्तों का भी अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-1 की कडिका-6 (iv) में भी यह निदेश निर्गत है कि बोली गई उच्चतम ठाक राशि परशधन वर्ष के लिए बंदोबस्

ती राशि मानी जायेगी,द्वितीय तथा उसके आगे के वर्षों की चंदोबस्ती राशि उक्त वर्ष के पूर्व के बंदोबस्ती राशि के 120% के समतुल्य होगी। वर्णित प्रावधानों से स्पष्ट है कि बंदोबस्तधारी निविदा समर्पित करने के समय ही इस तथ्य से अवगत है कि प्रत्येक वर्ष की चंदोबस्ती राशि पूर्व के वर्षों के 120% के समतुल्य होगी। सहरसा जिला के राम्पूर्ण जिला की चंदोबस्ती पंचाग वर्ष 2018 से वर्ष 2019 तक के लिए कराई गयी है। इसलिए वर्ष 2016 ही बंदोबस्ती अवधि के लिए प्रथम वर्ष मानी जायेगी।

आवेदन के दूसरे बिन्दु के संबंध में निम्न प्रावधान व उल्लेख आवश्यक है-

निविदा दस्तावेज की कंडिका-19 (vii) में खनिज की अनुपलब्धता मार्ग व्यकधान,सीमाना से संबंधीत कोई व्यावधान अथवा अन्यान्य कारण से उत्तोलन में बाधा उत्पन्न होने पर सरकार द्वारा कोई अति देव नहीं होगी।खान निरीक्षक,सहरसा द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख है कि आवेदनकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति की नांग जित्त अवधि के लिए की जा रही है,उस अवधि में खनन कार्य पर कोई प्रतिबंध अधिरोपित नहीं था।चूंकि चंदोबस्ती की अवधि 31.13.2019 तक के लिए मान्य है तथा बंदोबस्तधारी की किसी त्रिटु अथवा अनियमितता के चलते प्रेषण प्रभावित हुआ तो भी बंदोवरतधारी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति ने निर्धारित खनिज की अधिकतम मात्रा का उत्खनन/प्रेषण उक्त तिथि तक कभी भी कर

सकते हैं। अतः वंदोबस्तधारी के क्षतिपूर्ति का दावा निविदा दस्तावेज की कडिका 19 (xii) के आलोक न स्वकार्य योग्य नहीं है। उपरोक्त के अनुसार या अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।" भगवद देशवेज के प्रति पक्ष देश के प्रदेश पर राज्यपाल कर सकते हैं जवाब देने वाले हैं। भले ही यह बालूघाटों के बंधारण के लिए उपयुक्त होता है और 2016 में भी ऐसा ही हुआ। आबादी राष्ट्र के 120% के समतुल्य होगी. पाट्टीयर खण्डका 12 में बड़ोकटीधारी दारा भागान की प्रक्रिया का उपयोग है। (viii) यह जो कुछ भी हो सकता है वह जो कुछ भी हो सकता है जो कुछ भी हो सकता है। आप से पालन करना होगा। एक लक्ष्य प्राप्ति के संदर्भ में-1 की कल्पना-6 (iv) में भी यह देश बन जाता है। उस समय बड़ी आबादी वाली प्रदेश की मन की बात होती है, उस समय की बात होती है, जब देश की राजनीति में बदलाव आता है, तो उस समय की बात है। 2018 का पटना उच्च न्यायालय सी. डब्ल्यू. जे. सी. आई. डी. 1 डी.1 <आई.डी. उत्तरान होने पर सरकार दारा को अब्त देव नहीं होगी। अगर आप किसी भी देश की जनता के बारे में बात नहीं करते हैं, तो क्या होगा? इसलिए यह वर्ष 2018 के पटना उच्च न्यायालय के सी. डब्ल्यू. जे. सी. आई. डी. 1 आई. डी.भी बांद्रिवर्ती सशक्तिकरण का उद्देश्य उत्तर भारत का उत्तर भारत (19 उत्तर प्रदेश का 19 (xii) के

अलग न हो सकता है और न हो सकता है। देश की प्रभुता भी सशक्त को भीज दी जाए " ।

36. जहाँ तक दूसरे भाग में उस संक्षिप्त अवधि के बारे में, जिसके बारे में याचिकाकर्ता का दावा है कि खनन कार्य अवरुद्ध कर दिया गया था, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि नियमों और शर्तों को देखते हुए, वह मामले को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हालांकि, जहां तक 2016 को आधार वर्ष मानते हुए अतिरिक्त 20 प्रतिशत की मांग का संबंध है, आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि प्रतिवादी, प्रधान सचिव ने 2017 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 6526 में समन्वय पीठ के आदेश को देखने की भी परवाह नहीं की है।

37. दिनांक 10/11/2017 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता 2016 में एक भी दिन के लिए रेतघाटों का संचालन नहीं कर सका क्योंकि खनन विभाग ने खनन योजना अनुमोदन में देरी की थी। जिसे 27.12.2016 पर जारी किया गया था और राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, बि द्वारा पर्यावरण मंजूरी देने में देरी को कायम रखा गया था। फिर भी, राज्य याचिकाकर्ता को लाभ से वंचित करके और बिना किसी गलती के उसे दंडित करके उस राशि को जेब में डालने का इरादा रखता है।

38. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, प्रधान सचिव इस पहलू पर गौर करने में विफल रहे, हालांकि विशेष पी. पी. माइंस ने प्रस्तुत किया कि एक बार इस न्यायालय का दूसरा आदेश आया जिसके द्वारा प्रधान सचिव को मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था, तो पहले आदेश का इसके साथ विलय हो गया। यह न्यायालय सुरक्षित रूप से यह देख सकता है कि इस तथ्य की पृष्ठभूमि में कि दिनांकित उक्त आदेश को न तो अधिकारियों द्वारा चुनौती दी गई थी और न ही दरकिनार कर दिया गया था, उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत विलय सिद्धांत बेतुका है, कम से कम कहने के लिए। प्रधान सचिव आदेश पारित करने से पहले 10.11.2017 दिनांकित आदेश को देखने के लिए कर्तव्यबद्ध थे।

39. श्री अमन सेठी (सुप्रा) का आदेश निश्चित रूप से वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है जैसा कि विद्वान विशेष लोक अभियोजक, खान ने बताया है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के पक्ष में पटना उच्च न्यायालय का दिनांक 10.11.2017 का सकारात्मक आदेश है जिसे प्रतिवादियों द्वारा जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है।

40. मान लीजिए, याचिकाकर्ता CWJC No- 6526 2017 का (याचिका का अनुलग्नक-9) और रिट कोर्ट ने 10.11.2017 दिनांकित एक आदेश के माध्यम से स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता को छूट देने का आदेश दिया। इस आदेश को न तो चुनौती दी गई और न ही दरकिनार कर दिया गया।

41. उस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध/मांग को श्री अमन सेठी (सुप्रा) मामले में खंड पीठ के फैसले के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है। इस मामले के तथ्य और परिस्थितियों श्री अमन सेठी (सुप्रा) मामले से बहुत अलग हैं।

42. इस न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के दो आदेशों और प्रतिवादी, प्रधान सचिव द्वारा लिए गए निर्णय का भी संज्ञान लिया है। याचिकाकर्ता के अनुरोध को खारिज करने के प्रतिवादी के निर्णय में, जिसमें वर्ष 2016 को आधार वर्ष मानकर 120% भुगतान करने के लिए बाध्य न करने का अनुरोध किया गया था, उपरोक्त तथ्यों के आलोक में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। प्रतिवादी अधिकारी वर्ष 2016 में खनन कार्य शुरू करने के लिए समय पर आवश्यक मंजूरी आदेश देने में विफल रहे हैं, इसलिए याचिकाकर्ता को उसके द्वारा हस्ताक्षरित विभिन्न धाराओं का बहाना बनाकर भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जहां तक 20% की बढ़ी हुई राशि का संबंध है, वह वर्ष 2017 को आधार वर्ष मानकर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि वास्तविक संचालन प्रतिवादियों द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंजूरी के अनुसार हुआ था। जहां तक अन्य मांगों का संबंध है, याचिकाकर्ता उन धाराओं के अनुरूप भुगतान करने के लिए बाध्य होगा, जिन्हें उसने स्वीकार किया है।

43. तदनुसार आदेश दिया गया। प्रतिवादी संख्या 2 के दिनांक 05.11.2018 के आदेश, जिसमें 20% वृद्धि के लिए आधार वर्ष 2016 के स्थान

पर वर्ष 2017 मानने के संबंध में याचिकाकर्ता के दावे को खारिज किया गया था, को अपास्त किया जाता है। वह प्रथम वर्ष को 2017 मानते हुए 20% की बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह एक बार फिर स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को यह रियायत केवल बढ़ी हुई 20% की राशि के भुगतान के संबंध में दी गई है। अन्य सभी देनदारियों के लिए, वह नियमों और शर्तों के अनुसार भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

44. रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त टिप्पणियों के साथ किया जाता है।

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

किरण/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।